www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 168 | जौनपुर सोमवार, 02 फरवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

हिमाचल प्रदेश के सीएम ने मनरेगा में बदलाव के विरोध में दो घंटे का उपवास रखा

शिमला, (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कैबिनेट सहयोगियों और पार्टी नेताओं के साथ शुक्रवार को राज्य की राजधानी के ऐतिहासिक रिज ग्राउंड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें बदलाव किए जाने के विरोध में सुबह 11 बजे से दो घंटे का उपवास रखा।मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने न केवल मनरेगा का नाम बदला है, बल्कि इस योजना की मूल भावना को भी कमजोर किया है। उन्होंने पहले कहा था कि इस योजना ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए थे, लेकिन अब रोजगार के अवसर कम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि पहले ग्राम प्रधानों को मनरेगा के तहत सड़क निर्माण जैसे कार्यों को करने का अधिकार प्राप्त था, जिससे लोगों के घरों के पास रोजगार सुनिश्चित होता था और कोविड–19 महामारी के दौरान इस योजना ने लोगों को अधिकतम रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

देशभर में कश्मीरियों पर हमले रोकें सरकार

श्रीनगर। कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक ने शुक्रवार को अधिकारियों से घाटी के बाहर रहने वाले कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मीरवाइज ने यहां ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के विकास नगर इलाके में आठ साल के कश्मीरी शॉल बेचने वाले ताबिश और उसके भाई दानिश पर लोहे की रॉड से हुए हमले पर दुख और चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह घटना जम्मू–कश्मीर के बाहर आम कश्मीरियों को होने वाली सांप्रदायिक भेदभाव और दुश्मनी के परेशान करने वाले पैटर्न को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से कश्मीरी व्यापारियों, श्रमिकों और विद्यार्थियों पर उत्पीड़न और हमलों की ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि हजारों कश्मीरी सर्दियों के महीनों में ईमानदारी से रोजी–रोटी कमाने के लिए अलग–अलग राज्यों में जाते हैं, और ऐसे कमजोर लोगों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। नरमपंथी अलगाववादी समूह के नेता ने कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद भारत के अलग–अलग हिस्सों में पढ़ने और काम करने वाले कश्मीरी विद्यार्थियों , व्यापारियों, पेशेवरों और अन्य लोगों की सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उनमें और उनके परिवारों में चिंता और डर पैदा होता है। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेने और बाहर रहने वाले कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की पर्यावरण संरक्षण प्रतिबद्धता को मिल रही वैश्विक पहचान : सीएम योगी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एटा की पटना बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिलने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को लगातार वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ष्एटा की पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात के कच्छ में स्थित छारी–ढांड को रामसर साइट्स में शामिल करना पॉलिसी, सुरक्षा और संरक्षण की एक यात्रा को दिखाता है, जहां इकोलॉजी और विकास साथ–साथ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आगे लिखा, यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान सतत संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता की रक्षा के प्रति भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। एटा के लोगों और वेटलैंड संरक्षण के लिए समर्पित सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई।ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में छारी–ढंड को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। भूपेंद्र यादव ने दो फरवरी को शविश्व वेटलैंड्स दिवसश से पहले भारत के रामसर नेटवर्क में दो नई वेटलैंड्स को शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने श्एक्सश पोस्ट में लिखा, विश्व वेटलैंड दिवस नजदीक होने के कारण मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत के बढ़ते रामसर नेटवर्क में दो नए नाम जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ में छारी–ढांड प्रतिष्ठित रामसर साइटों की सूची में नए नाम हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि ये मान्यताएं जैव विविधता को संरक्षित करने और महत्वपूर्ण इकोसिस्टम की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर लिखा, खुशी है कि एटा (उत्तर प्रदेश) में पटना पक्षी अभयारण्य और कच्छ (गुजरात) में छारी–ढांड रामसर साइट बन गए हैं।

मध्य प्रदेश में वन पर्यटन पर जोर : मोहन यादव

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में जंगलों के बीच रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाने और आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वन पर्यटन पर जोर दिया जा रहा है। राजधानी भोपाल में आयोजित भारतीय वन सेवा अधिकारियों की मीट में हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि वन पर्यटन के जरिए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है। जो वनों के अंदर ग्रामीण जन रहते हैं, उनकी आय के साधन बढ़ाने के लिए जनजाति के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव ने आगे कहा कि देश के सबसे अच्छे विभागों में से राज्य का वन विभाग है। वन विभाग के प्रयास से चीता जैसे प्रोजेक्ट से लेकर वन्य प्राणियों के संरक्षण की दिशा में वन विभाग ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है। सबसे बड़ा टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, घड़ियाल– मगरमच्छ कई प्रकार के वन्य जीवों को संवारते हुए राज्य को दो नए टाइगर अभ्यारण दो साल में मिलने का सौभाग्य मिला है, जल्दी ही असम से जंगली भैंसा भी लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है समृद्ध मध्य प्रदेश में वन संपदा के संरक्षण का जो दौर चल रहा है वह आगे भी चलता रहेगा। बीते सालों में नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़े थे, आने वाले समय में चंबल में घड़ियाल छोड़े जाने हैं। कछुए की भी बहुत अच्छी प्रजाति संवर्धन का काम राज्य सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि राज्य में टाइगर के साथ हाथी भी स्थाई रूप से हमारे यहां बसेरा कर चुके हैं। हाथियों के संरक्षण के लिए वन अमले को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे है। पिछले सालों की तुलना में 10 प्रतिशत से भी काम दुर्घटनाएं हुई है, 90 प्रतिशत घटनाओं में कमी आई है। इस दिशा में और अच्छे काम किए जाएं इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।

2026 में बंगाल में बदलाव तय : अमित शाह

कोलकाता, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में आयोजित एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस की विदाई तय है और साल 2026 राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में सरकार बनाना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हो गया है। अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ बढ़ती जा रही है, वह अब केवल राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने जानबूझकर सीमा सुरक्षा को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए केंद्र सरकार जब जमीन मांगती रही, तब ममता बनर्जी जमीन देने से इनकार करती रहीं। इसके चलते सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा नहीं हो सका। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन और पुलिस घुसपैठियों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को न तो पटवारी रोकते हैं, न पुलिस, बल्कि उन्हें फर्जी दस्तावेज बनवाकर पूरे देश में भेजा जाता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब संसद में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, तब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इसका विरोध किया था। अमित शाह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि ममता बनर्जी सरकार बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने में सहयोग नहीं कर रही थी। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीएसएफ को तय समयसीमा के भीतर जमीन दी जाए ताकि सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा सके। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी माटी और मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थीं, लेकिन आज महिलाएं असुरक्षित हैं, जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा है और आम लोग तृणमूल सिंडिकेट से परेशान हैं। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए।

पीएम मोदी ने आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण और हलवारा एयरपोर्ट टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पंजाब का दौरा करेंगे। वे दोपहर लगभग 3रू45 बजे आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वे एयरपोर्ट के नए नाम श्श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट, आदमपुरश का अनावरण करेंगे। वे पंजाब के लुधियाना में हलवारा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के शुभ अवसर पर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलना उस संत और समाज सुधारक का सम्मान है, जिनकी समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं भारत के सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करती रहती हैं। पीएम कार्यालय के अनुसार, पंजाब में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी रविवार को हलवारा एयरपोर्ट पर जिस टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, वह राज्य के लिए एक नया गेटवे स्थापित करेगी। इससे लुधियाना और उसके आसपास के औद्योगिक व कृषि क्षेत्रों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। लुधियाना जिले में स्थित हलवारा एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय वायुसेना स्टेशन भी है। लुधियाना में पहले के एयरपोर्ट पर रनवे छोटा था, जो छोटे आकार के विमानों के लिए था। कनेक्टिविटी में सुधार करने और बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए हलवारा में एक नया सिविल एन्क्लेव बनाया गया है, जिसमें एक लंबा रनवे है जो ए320–जैसे विमानों को संभालने में सक्षम है।बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के सतत और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकास के विजन के अनुरूप टर्मिनल में कई हरित और ऊर्जा–कुशल सुविधाएं शामिल हैं, जिनमें एलईडी लाइटिंग, इंसुलेटेड छत, रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, सीवेज व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और लैंडस्केपिंग के लिए रिसाइकल वाटर का उपयोग शामिल है। आर्टिटेक्चरल डिजाइन पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।

गोडसे के वारिसों को सिखायेंगे सबक : स्टालिन

चेन्नई, (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) पर हमला तेज करते हुए शुक्रवार को कहा कि गांधी की जमीन को बचाने के लिए गोडसे के वारिसों को करारा सबक सिखाना होगा, जो देश को बर्बाद करने और महात्मा को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।श्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, "आइए हम सांप्रदायिक नफरत को खत्म करें! महात्मा का आदर करें! दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (जो गोडसे की गोलियों का शिकार हुए और जिन्होंने लोगों के बीच एकता को स्थापित करने की कोशिश की) वे हर भारतीय के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे!उन्होंने कहा, " गोडसे के वारिस न केवल महात्मा को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि देश को भी बर्बाद करने की कोशिश भी कर रहे हैं।" सांप्रदायिक ताकतों' को हराने का भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा, "हम साथ मिलकर जीतेंगे।इससे पहले, एक खबरिया चौलन के कार्यक्रम में श्री स्टालिन ने वंशवाद की राजनीति, अपने पुत्रों उदयनिधि स्टालिन को उपमुख्यमंत्री बनाने और द्रमुक के खिलाफ भ्रष्टाचार के भाजपा के आरोपों को बेकार का बहाना बताया। उन्होंने कहा, "ये बेबुनियाद आरोप पुरानी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं, जो वॉट्सऐप यूनिवर्सिटी के जरिये फैलायी जा रही हैं। उन्होंने अपनी द्रविड़ मॉडल डीएमके सरकार की शुरू की गयी कुछ खास योजनाओं का जिक्र किया, जिनसे समाज के अलग–अलग वर्गों को फायदा हो रहा है, जिनमें छात्र, बच्चे और अन्य शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जवाब बार–बार दिया जा चुका है। कोई भी राजनीति में आने के लिए आजाद है। लेकिन, सफल होने के लिए उन्हें लोगों का सामना करना होगा। उनका भरोसा जीतना होगा और चुनाव जीतना होगा। उन्होंने कहा, ष्यह उन लोगों की फैलायी झूठी खबर है, जो जमीन पर हमारा सामना नहीं कर सके। उन्होंने पूछा, ष्क्या हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप साबित हुआ है?ष साथ में भाजपा पर अन्नाद्रमुक से हाथ मिलाने का आरोप लगाया, जिसे शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया है।उन्होंने दागी राजनेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप या तो दब जाते हैं या उन पर कार्रवाई धीमी हो जाती है।

प्रगति प्लेटफॉर्म विकसित भारत की दिशा में सशक्त माध्यम : सीएम सैनी

चंडीगढ़, (एजेंसी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म श्प्रगतिश की सराहना करते हुए कहा है कि यह मंच विकास परियोजनाओं को गति देने और जन शिकायतों के त्वरित समाधान में अहम भूमिका निभा रहा है।श्री सैनी ने शुक्रवार को कहा कि यह प्लेटफॉर्म केंद्र, राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ–साथ योजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी को संभव बनाता है। उन्होंने कहा कि श्प्रगतिश पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुखी शासन का प्रतीक है। यह विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। इसके माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन और लाभों का प्रभावी वितरण सुनिश्चित हुआ है।श्री सैनी ने बताया कि हरियाणा में कुल 112 प्रमुख परियोजनाएं निगरानी में हैं। इनमें से 57 परियोजनाएं पूरी होकर चालू हो चुकी हैं। शेष 55 परियोजनाएं 5.44 लाख करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन हैं। चालू परियोजनाओं में से 13 परियोजनाओं की समीक्षा प्रगति मंच पर की गई। इनमें सड़क एवं राजमार्ग तेल एवं गैस बिजली रेलवे और रियल एस्टेट से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इससे जिनसे राज्य की कनेक्टिविटी और औद्योगिक ढांचे को मजबूती मिली है।

राहुल गांधी की नाराजगी के बाद कांग्रेस ने तेज किया संगठन विस्तार

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कार्यकारिणी का गठन अटका हुआ था, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हिदायत के बाद जिला इकाई की कार्यकारिणी के ऐलान का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल, राज्य में संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई। उसके बाद कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया था। इसकी वजह आपसी खींचतान बताई जा रही है। दो दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राज्य के नेताओं की बैठक हुई, और इस बैठक में भी कार्यकारिणी के गठन का मसला उठा।राहुल गांधी ने भी इस पर नाराजगी जताई थी। कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव डॉ. संजय कामले ने बताया है कि जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा, मऊगंज एवं सागर की जिला कार्यकारिणियों का गठन किया गया है। डॉ. कामले ने बताया कि कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया निरंतर जारी है तथा आने वाले समय में समस्त जिलों में भी जिला कार्यकारिणियों का गठन किया जाएगा। वर्तमान में कांग्रेस का संगठनात्मक कार्य पूरे प्रदेश में तेजी और सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहा है।उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित समस्त प्रकोष्ठों के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों की नियुक्तियां भी की गई हैं, ताकि समाज के हर वर्ग की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, जिला कांग्रेस कमेटियों में जिला संगठन महासचिवों की नियुक्ति कर संगठनात्मक समन्वय और कार्यक्षमता को और सुदृढ़ किया गया है। पार्टी ने तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिए है।

नक्सल मुक्त बस्तर-सुरक्षित छत्तीसगढ़ यही हमारा संकल्प है : सीएम विष्णुदेव साय

रायपुर, (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके के चार सक्रिय माओवादी कैडरों ने शुक्रवार को सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अहम आत्मसमर्पण और पुनर्वास प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ माओवादी मुक्त बस्तर की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ष्नक्सल मुक्त बस्तर और सुरक्षित छत्तीसगढ़ हमारा संकल्प है।किस्टाराम क्षेत्र में 8 लाख के इनामी 4 सक्रिय माओवादी कैडरों द्वारा हिंसा का मार्ग त्यागकर मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय बस्तर में बढ़ते विश्वास, सुरक्षा और विकास के वातावरण का स्पष्ट संकेत है। सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयास, सुदृढ़ कैम्प व्यवस्था और बेहतर कनेक्टिविटी से माओवादी प्रभाव क्षेत्र लगातार सिमट रहा है और उनका आधार कमजोर हो रहा है। दरअसल, बस्तर क्षेत्र से नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके के चार सक्रिय माओवादी कैडरों ने शुक्रवार को सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।इनमें से प्रत्येक पर 8 लाख रुपए का इनाम था, जो प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) नेटवर्क में उनके दबदबे को दर्शाता है। यह आत्मसमर्पण 2026 की शुरुआत में बस्तर में माओवादी दलबदल की एक व्यापक लहर के बीच हुआ है, जिसमें राज्य की पुनर्वास पहलों के तहत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिंसा छोड़ दी है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं नक्सली ताकत के कमजोर पड़ने का संकेत हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य 31 मार्च तक माओवादी मुक्त छत्तीसगढ़ हासिल करना है।इन सुरक्षा संबंधी उपलब्धियों के पूरक के रूप में, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के सुचारू पुनएकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सक्रिय पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया है।

संपादकीय

मोदी- दोनों हाथों में लड्डू

जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए चाहे जितने कठोर नियम बना ले, उन्हें लागू करना आसान नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ भी। यूजीसी द्वारा जारी नए नियमों पर देश भर में सवाल और बवाल दोनों खड़े हुए और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसे रोकने के लिए याचिकाएं दायर हुईं, जिन पर गुरुवार 29 जनवरी को महत्वपूर्ण सुनवाई भी हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अस्थायी रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पहले दृष्टिकोण से यह प्रतीत होता है कि इन नियमों की भाषा में स्पष्टता की कमी है, जिससे उनका गलत उपयोग हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चेतावनी दी कि ऐसे नियम समाज को विभाजित कर सकते हैं और परिसरों में अमेरिका की तरह नस्लीय विभाजन जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन नियमों की जांच की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका दुरुपयोग न हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन नियमों की समीक्षा करने को कहा और तब तक उनके लागू होने पर रोक जारी रखने का आदेश दिया। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वे एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करें। जिसमें कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करने पर विचार किया जाए, ताकि समाज में बिना भेदभाव के समग्र विकास हो सके।गौरतलब है कि यूजीसी नियमावली, 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था। ये नियम अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्रों के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लाए गए हैं। यह 2012 के पुराने नियमों की जगह लाए गए हैं। इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता समितियां (इक्विटी कमेटी) गठित करना अनिवार्य किया गया है। इस कमेटी का काम जातिगत भेदभाव की शिकायतों की जांच करना है। लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के हक की बात उठते ही समाज में बवाल खड़ा हो गया।भारत में जाति व्यवस्था इतनी गहरी पैठी हुई है कि जाति के नाम पर उत्पीड़न सामान्य व्यवहार के तौर पर अपना लिया गया है। एक इंसान दूसरे इंसान को केवल जाति के आधार पर अपमानित, शोषित या प्रताड़ित करे, यह चलन सदियों से चला आ रहा है और इसे दूर करने की जितनी कोशिशें की गईं, उतने ज्यादा अड़ंगे सवर्ण समाज की तरफ से लगाए गए। चाहे मंडल कमीशन की सिफारिशें हों या अभी यूजीसी के नए नियम, उन पर समाज का एक तबका ऐसे विरोध में उतरा मानो अपने से निचली जातियों का उत्पीड़न उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण वर्ग की ओर से दायर याचिकाओं में इन नियमों को असंवैधानिक बताया गया है। इसे जाति आधारित भेदभाव करार दिया। याचिकाकर्ताओं में से एक वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है और इससे शिक्षा क्षेत्र में, समाज में और अधिक खाई पैदा हो सकती है। कितने कमाल की बात है कि शिक्षा क्षेत्र या समाज में जातिगत भेदभाव इन लोगों को तब दिखाई नहीं देता, जब किसी दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन में अलग पंक्ति में बिठाने की खबरें आती हैं, या किसी छात्र को उसकी निचली जाति के कारण शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। रोहित वेमुला या पायल तड़वी जैसे लोगों को अगर आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया,।

अर्थजगत का मायावी खेल

हम चीन के साथ जाएं तब मुश्किल और अमेरिका से बंधे रहें तो और मुश्किल। और इसी जुड़ाव की कीमत हमारा रुपया भी दे रहा है जो दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के आगे डालर से भी ज्यादा तेजी से लुढ़क रहा है। मोदी जी भूल गए होंगे यह संभव नहीं लगता लेकिन हाल फिलहाल डालर कभी चालीस रुपए में मिलेगा इसकी संभावना तो दूर–दूर तक नहीं दिखती। यह आर्थिक मामलों में यथार्थ और माया के खेल को समझने का बहुत बढ़िया अवसर है और हम चाहें तो इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को धन्यवाद कह सकते हैं। वैसे वे खुद क्या हैं और आर्थिक मामलों में किस तीसरी चीज को हासिल करना चाहते हैं यह समझना मुश्किल है। वे तो क्रिप्टो करेंसी से लेकर और जाने किन चीजों के सौदागर हैं– खुद को शांति का सौदागर तो बताते ही हैं। आज जिस तरह शेयर बाजार, वित्तीय बाजार, करेंसी बाजार और बुलियन बाजार में अफरातफरी मची है वह बताती है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और काम काज से इनका बहुत कुछ लेना नहीं है। भारत ही दुनिया की आर्थिक गतिविधियों में कोई बड़ा उतार–चढ़ाव, खास तौर से गिरावट दिखाई नहीं देती लेकिन शेयर बाजार धड़ाम हो रहे हैं, करेंसी का उतार–चढ़ाव संभालने में सरकारों के पसीने छूट रहे हैं, निवेश बाजार से पूंजी निकालने और बाहर ले जाने की होड़ लगी है और बुलियन बाजार में आग लगी है। सोना–चांदी ही नहीं प्लेटिनम समेत सारे कीमती धातु रिकार्ड ऊंचाई पर हैं और मांग बढ़ती जा रही है। सोना और चांदी की कीमतें इस स्तर पर आ गई हैं कि आम आदमी के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल है और जिनको सोने–चांदी से कोई लेना–देना नहीं रहा है वे किसी भी कीमत पर इनको खरीदकर जमा करते जा रहे हैं। और माया की तरह यह कहना भी आसान नहीं है कि इन गतिविधियों से अर्थव्यवस्था अप्रभावित है। उस पर भी खूब असर पड़ रहा है लेकिन खैरियत यही है कि महामंदी का कोई नया दौर आता नहीं दिखाता। पर मंदी कोई सूचना देकर थोड़े ही आती है।यह माना जाता है की हमारा शेयर बाजार बहुत बड़ा नहीं है और इसमें देश–विदेश का जो पैसा लगा है उसमें काफी बड़े खिलाड़ी हैं। वे बाजार को कृत्रिम तरीकों से भी ऊंचा बनाए रखते हैं या सरकार में अपने ऊंचे रसूख से सरकारी बैंकों और बीमा तथा भविष्यनिधि समेत अन्य वित्तीय संस्थाओं से निवेश कराके बाजार को संभालते रहते हैं। वैसे यह सरकार की जवाबदेही भी है। इधर यह भी हुआ है कि विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर अपना निवेश वापस ले रहे हैं पर इधर देसी निवेश बढ़ाने से बाजार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन ट्रम्प महाराज के फैसले हंगामा मचाते रहे हैं और इस बार जब उन्होंने 500 फीसदी तक सीमा शुल्क बढ़ाने की बात उठाई तो सारे बाजारों का धीरज चूक गया। धड़ाम हमारे बाजार भी हुए लेकिन इस बार बचाने का प्रयास करने वाले भी नदारद रहे। हमारी सरकार के दुलारे अदानी पर कार्रवाई की अमेरिकी पहल ने एक दिन में उनकी कई कंपनियों के शेयर में पंद्रह फीसदी तक की गिरावट ला दी। अकेले जनवरी में महीने में अब तक बाजार साढ़े चार फीसदी तक टूट चुका है और अब सभी बजट की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कोई चमत्कार कर सकती हैं इसकी गुंजाइश कम ही लगती है।सरकार और रिजर्व बैंक ने जब रुपए की गिरावट रोकने का प्रयास किया तब ज्यादा सफलता नहीं मिली। जनवरी भर में करीब 2.7 अरब डालर की विदेशी मुद्रा बाजार में उतार कर सरकार ने अपने दम भर प्रयास किया लेकिन वह सिर्फ गिरावट की रफ्तार को कम कर सकी, गिरावट को रोकना संभव नहीं हुआ। डालर 91 रुपए के ऊपर पहुंचा तो यूरो 103 से ऊपर और पाउंड 125 के करीब। यह तब है जब रूस के तेल का भुगतान डालर में नहीं करना होता। डालर के उतार–चढ़ाव पर मोदी जी ने ही पहले काफी कुछ कहा है इसलिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन मोदी सरकार इस तरह बेबस हो जाएगी, इसका कारण ट्रम्प की नीतियों की अनिश्चितता भर नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था में और आसपास के देशों की आर्थिक गतिविधियों में भी काफी कुछ बदल रहा है जो डालर को मजबूत बनाए न बनाए हमारे रुपए को कमजोर करता जा रहा है।

टैरिफ के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका से आगे निकलता शेष विश्व

प्रह्लाद

दिनांक 20 जनवरी 2025 को डॉनल्ड ट्रम्प अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनाए गए थे। वर्ष 2024 में ट्रम्प ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव "डांम ।उमतपबं ळतमंज ।हंपद" अर्थात "अमेरिका को पुनः महान बनाएं", नारे के साथ जीता था। वर्ष 2025 का पूरा वर्ष भर पूरे विश्व ने ट्रम्प को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए देखा। लगभग पूरा 2025 का वर्ष ट्रम्प ने विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले उत्पादों के आयात पर टैरिफ लगाते हुए बिताया और मित्र देशों सहित कई देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर भारी भरकम टैरिफ लगाए। ट्रम्प का सोचना था कि टैरिफ को बढ़ाकर वे अन्य देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात को कम करेंगे और इससे अमेरिका में ही इन उत्पादों का उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। ट्रम्प का संभवतरू यह सोचना था कि उनका यह प्रयास अमेरिका को महान बनाते हुए शेष विश्व को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। परंतु, वर्ष 2025 में अमेरिका एवं शेष विश्व के आर्थिक क्षेत्र के आंकडें देखने पर ध्यान में आता है कि अमेरिका के मित्र राष्ट्रों सहित विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ का असर अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर लगभग नहीं के बराबर पड़ा है। बल्कि, इसका खामियाजा अमेरिका के नागरिकों को भुगतना पड़ा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से अमेरिका में उत्पादों की कीमतों में बेतहाशा बृद्धि दर्ज हुई है, इससे मुद्रा स्फीति में वृद्धि तेज हुई है एवं अमेरिकी नागरिकों को विभिन्न उत्पादों को बढ़ी हुई कीमतों दरों पर खरीदना पड़ रहा है। अमेरिकी नागरिक पिछले 5 वर्षों की तुलना में आज खाद्य सामग्री पर 30 प्रतिशत अधिक खर्च कर रहे हैं। अमेरिका में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें 22 प्रतिशत से बढ़ चुकी हैं। खाद्य पदार्थों एवं मकान की कीमतों में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई हैं। अमेरिका में मुद्रा स्फीति की दर भी 3 से 4 प्रतिशत के बीच बनी हुई है, जो पिछले कई वर्षों की तुलना में बहुत अधिक है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से परेशान हो रहा है अमेरिकी नागरिक, न कि अन्य कोई देश। श्री रुचिर शर्मा, भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक एवं फायनैन्शल टाइम्स के स्तम्भ लेखक, ने अपने एक साक्षात्कार में कई आंकडें दिए हैं, जिनका प्रयोग इस लेख को तैयार करने में किया गया है। अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले आयात पर लगाए गए टैरिफ के पश्चात अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कम होती हुई दिखाई दे रही है। वर्ष 2024 में अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत की रही थी जो वर्ष 2025 में घटकर 2.1 प्रतिशत हो गई। जबकि वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर दोनों वर्षों, 2024 एवं 2025, में 2.8 प्रतिशत बनी रही है। वर्ष 2025 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में किसी प्रकार की कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024 में वृद्धि दर, 6.5 प्रतिशत की रही थी, जो वर्ष वर्ष 2025 में बढ़कर 7.2 प्रतिशत की हो गई। वर्ष 2024 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से 52 प्रतिशत देशों की प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद में वृद्धि दर अमेरिका की तुलना में अधिक रही थी जबकि वर्ष 2025 में 76 प्रतिशत देशों की प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद में वृद्धि दर अमेरिका की तुलना में अधिक रही है। वर्ष 2025 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास दर तेज गति बढ़ती हुई पाई गई है। इस प्रकार, अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के बावजूद शेष विश्व में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर अमेरिका से अधिक रही है। इस प्रकार अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का प्रभाव अन्य देशों के विकास पर विपरीत रूप से नहीं पड़ा है। अमेरिका के पूंजी (शेयर) बाजार में भी वर्ष 2025 में निवेशकों को अपने निवेश पर कम आय प्राप्त हुई है। अमेरिका में निवेशकों द्वारा पूंजी (शेयर) बाजार में किए गए निवेश पर 18 प्रतिशत की आय का अर्जन हुआ है। जबकि, यूरोप में निवेशकों को 35 प्रतिशत, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में निवेशकों को 34 प्रतिशत, अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व में निवेशकों को 32 प्रतिशत एवं चीन में निवेशकों को 31 प्रतिशत की आय अर्जित हुई है। इस प्रकार, अमेरिका की तुलना में अन्य देशों में पूंजी (शेयर) बाजार में निवेशकों को लगभग दुगनी आय अर्जित हुई है। अमेरिकी नागरिकों का पूंजी (शेयर) बाजार में निवेश तुलनात्मक रूप से अधिक है। अमेरिकी नागरिकों का जायदाद में निवेश 30 प्रतिशत है जबकि शेयर बाजार में 32 प्रतिशत निवेश है। चीन के नागरिकों का जायदाद में निवेश 55 प्रतिशत एवं शेयर बाजार में निवेश केवल 11 प्रतिशत है। इसी प्रकार, यूरोप के नागरिकों का निवेश क्रमश 57 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत है। भारतीय नागरिकों के निवेश क्रमशरू 50 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत है। अमेरिका द्वारा अन्य देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर लगाए गए टैरिफ के चलते अमेरिका का राजकोषीय घाटा वर्ष 2024 के सकल घरेलू उत्पाद के 6.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2025 में 6 प्रतिशत हो गया है। एक रीसर्च प्रतिवेदन में यह तथ्य उभरकर भी सामने आया है कि टैरिफ के कारण अमेरिका में उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है एवं टैरिफ का लगभग 96 प्रतिशत भाग अमेरिकी नागरिकों द्वारा वहन किया गया है। इसके कारण अन्य देशों से अमेरिका को निर्यात कम नहीं हुए हैं। यूरोप का राजकोषीय घाटा वर्ष 2024 के 3.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 3.2 प्रतिशत हो गया है। उभर रही अर्थव्यवस्थाओं का राजकोषीय घाटा वर्ष 2024 के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 4.8 प्रतिशत हो गया है। पूर्व में विभिन्न देशों का राजकोषीय घाटा लगभग 3 प्रतिशत तक रहता आया है जबकि वर्तमान परिस्थितियों के मध्य, विभिन्न देशों का राजकोषीय घाटा बढ़ते हुए 6 प्रतिशत के स्तर तक रहने लगा है। यह स्थिति वित्तीय क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वर्ष 2025 में विदेशी व्यापार में वृद्धि दर भी अमेरिका की तुलना में अन्य देशों में अधिक रही है। अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व के निर्यात में वर्ष 2019 से 2024 के दौरान औसत 5 प्रतिशत की वृद्धि रही थी जो वर्ष 2025 में बढ़कर 6.4 प्रतिशत की हो गई है। जबकि अमेरिका से निर्यात में वृद्धि दर इसी अवधि के दौरान 4.6 प्रतिशत से गिरकर 4.1 प्रतिशत रह गई है। टैरिफ का अमेरिका से अन्य देशों को होने वाले निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जबकि अन्य देशों ने आपस में नए बाजारों की तलाश करते हुए अपने विदेशी व्यापार, विशेष रूप से निर्यात, में वृद्धि दर्ज की है। कई देशों ने आपस में मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं, इससे भी विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में वृद्धि दर्ज हुई है। अमेरिका से अन्य देशों को निर्यात के कम होने के चलते अमेरिका में चालू व्यापार खाता घाटा 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका में आज भी उत्पादन की तुलना में उपभोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। अमेरिका की टैरिफ नीति के चलते अमेरिका पुनः महान (ड ।ळ ।) बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु, विश्व के अन्य कई देश जरूर महान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः टैरिफ का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभवित करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि विश्व में अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार, ट्रम्प इस धरा को महान बनाने (डांम म्तजी ळतमंज ।हंपद – डम्ळ ।) में अपना योगदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर विपरीत परिस्थितियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ती हुई ।

तेल के खेल में मोदी के आगे कोई नहीं टिक सकता

नीरज

भारत और वेनेजुएला के बीच कूटनीति ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई टेलीफोन वार्ता ने वैश्विक ऊर्जा राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच हुई इस वार्ता का सीधा संबंध तेल से है और इसका परोक्ष असर भारत रूस निर्भरता घटाने, अमेरिका से व्यापारिक दबाव कम करने और ग्लोबल साउथ में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करने से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने भारत को संकेत दिया है कि वह शीघ्र ही वेनेजुएला से तेल खरीद दोबारा शुरू कर सकता है ताकि रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता घटे। यह पहल भारत अमेरिका ऊर्जा संबंधों को नए सांचे में ढालने की अमेरिकी कोशिश का हिस्सा है। रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले महीनों में भारत रूसी तेल आयात में प्रतिदिन कई लाख बैरल की कटौती कर सकता है। इस कूटनीतिक पृष्ठभूमि में डेल्सी रोड्रिगेज ने प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता के बाद ऊर्जा सहयोग पर सहमति की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक संदेश में कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय साझेदारी को सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की साझा दृष्टि रखते हैं। हम आपको बता दें कि यह वार्ता ऐसे समय हुई है जब वेनेजुएला ने अपने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है। दशकों तक कठोर सरकारी नियंत्रण के बाद अब कानूनों में व्यापक सुधार किए गए हैं। खोज, उत्पादन, वितरण और विपणन में निजी भागीदारी को अनुमति दी गई है। कर और रॉयल्टी घटाई गई हैं, बड़े प्रोजेक्ट के लिए शुल्क और कम किए जा सकते हैं और विवादों में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का रास्ता खोला गया है। इस तरह यह बदलाव कर पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के दौर की राष्ट्रीयकरण नीति को पलट दिया गया है। अमेरिका ने भी जवाबी कदम उठाते हुए वेनेजुएला को प्रतिबंधों में ढील दी है। नया सामान्य लाइसेंस अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के तेल के निर्यात, भंडारण, परिवहन और परिशोधन की अनुमति देता है, हालांकि भुगतान और कुछ देशों से जुड़े लेन–देन पर सख्त शर्तें रखी गई हैं। हम आपको याद दिला दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल मार्च में वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाया था, जिसमें भारत भी शामिल था। अब दिशा बदली है। देखा जाये तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अवसर का लाभ उठाते हुए सस्ता रूसी तेल बड़ी मात्रा में खरीदा। इससे देश की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी हुईं और कीमतों पर भी नियंत्रण रहा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका का दबाव बढ़ा है, व्यापार शुल्क भारी हुए हैं और प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति व्यवस्था जटिल हो गई है। इसी वजह से भारत अब तेल आयात के नए विकल्प तलाश रहा है। आयात के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में रूस से तेल खरीद दो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके साथ ही ओपेक देशों से आने वाले तेल की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। कई भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल से दूरी बना ली है और आपूर्ति स्रोत बदलने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच, वेनेजुएला के नए कानून ने एक नई संभावना खोली है। उत्पादन और निर्यात में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंधों के चलते जो तेल पहले मजबूरी में सस्ते दाम पर बेचना पड़ता था, अब वह बेहतर कीमत और कम लागत के साथ खुले बाजार में उपलब्ध होगा। सरकारी आकलन

के अनुसार, वेनेजुएला में इस साल उत्पादन में 18 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव है, जबकि निजी अनुमान इससे भी तेज उछाल की ओर संकेत कर रहे हैं। देखा जाये तो मोदी और रोड्रिगेज की बातचीत सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि सामरिक संकेत है। भारत साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि वह किसी एक स्रोत या किसी एक धड़े के साथ नहीं रहेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत की आर्थिक संप्रभुता की रीढ़ है और इस रीढ़ को मजबूत करने के लिए बहुध्रुवीय नीति अनिवार्य है। वेनेजुएला के दरवाजे खुलना भारत के लिए अवसर की तरह है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार तक पहुंच सस्ती और स्थिर आपूर्ति का रास्ता खोल सकती है। हालांकि भारत को अमेरिकी शर्तों, भुगतान नियमों और भू–राजनीति की रस्साकशी में संतुलन भी साधना होगा। सामरिक रूप से यह कदम रूस पर निर्भरता घटाकर भारत की सौदेबाजी की शक्ति को और बढ़ाता है। यदि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद फिर शुरू करता है तो अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम हो सकता है, साथ ही लैटिन अमेरिका में भारत की मौजूदगी मजबूत होगी। ग्लोबल साउथ के मंच पर भी यह संकेत जाएगा कि भारत ठोस साझेदारी करता है। वहीं वेनेजुएला ने नियम सरल कर यह दिखा दिया है कि आर्थिक यथार्थ विचारधारात्मक जिद से बड़ा होता है। निजी निवेश, कम कर, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और पारदर्शिता से ही उत्पादन बढ़ेगा और आम नागरिक तक लाभ पहुंचेगा। भारत यदि यहां निवेश और दीर्घकालिक खरीद समझौते करता है तो यह दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। हरहाल, इस पूरी तस्वीर के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल और दूरदर्शी विदेश नीति साफ दिखाई देती है। कच्चे तेल की खरीद और आपूर्ति के मोर्चे पर उन्होंने खुद को एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया है। जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल संकट से जूझ रही थी, तब भारत पर भी हर तरफ से दबाव था कि वह सस्ते रूसी तेल से दूरी बनाए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए बहुस्तरीय कूटनीति अपनाई। रूस से तेल खरीद जारी रखी, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से आपूर्ति संतुलित की और अब लैटिन अमेरिका की ओर रणनीतिक कदम बढ़ा दिये हैं। इसी संतुलित नीति का नतीजा रहा कि जहां यूरोप और अमेरिका में ईंधन के दाम आसमान छू रहे थे, वहीं भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काबू में रहीं। यह केवल आर्थिक प्रबंधन नहीं था, बल्कि वैश्विक दबावों के बीच भारत की सामरिक स्वायत्तता और नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन था। देखा जाये तो मौजूदा संकेत साफ बता रहे हैं कि नई दिल्ली लगातार कुशल रणनीति के साथ फैसले कर रही है। यही आक्रामक यथार्थवाद आज के दौर की मांग है।

बजट 2026-27 को वैश्विक उथल-पुथल के बीच स्थिर आर्थिक विकास का फायदा

अंजन

यह सबसे नया मुक्त व्यापार समझौता खास तौर पर मुश्किल है। यह कम से कम दो दशकों से बन रहा था। फिर भी, अचानक यह जादू की तरह हो गया। सभी मुश्किल मुद्दे भुला दिए गए और समझौता हो गया। ऊपर से देखने पर, यह आर्थिक रणनीति के ठोस हिस्से के बजाय मुख्य रूप से एक राजनयिक उपकरण के तौर पर काम का लगता है। 2026–27 का भारतीय बजट अशांत माहौल के बीच आ रहा है। वैश्विक उथल–पुथल के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था खुशी–खुशी आगे बढ़ रही है। आखिर, हर साल ऐसा नहीं होता कि किसी वित्त मंत्री को बजट तैयार करने का मौका तब मिले जब अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स का दौर हो, परी कथाओं की एक ऐसी नायिका का जो हर चीज को ठीक वैसा ही चाहती है जो उसके मनोनुकूल हो।ताजा आंकड़े खुद ही सब कुछ बताते हैंरू जीएसटी को आसान बनाने और त्योहारों पर होने वाले खर्च ने अक्टूबर–नवंबर के दौरान घरेलू मांग को बल दिया। ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है जबकि शहरी मांग में लगातार सुधार हो रहा है। निवेश की गतिविधि अच्छी बनी हुई है। निजी अंतिम उपभोक्ता खर्च (पीएफसीई) 2025–26 की दूसरी तिमाही में 7.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 2025–26 की पहली तिमाही में यह 7.0 प्रतिशत था। सकल अचल पूंजी का सृजन (जीएफसीएफ) भी 2025–26 की दूसरी तिमाही में 7.3प्रतिशत पर मजबूत बना रहा।भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। भारत के एक के बाद एक वित्त मंत्री और आर्थिक प्रशासकों के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक कीमतों की स्थिति रही है। बेकाबू कीमतों ने वित्त मंत्रियों को अपने बजट तैयार करते समय परेशान किया था। महंगाई की रणनीति ने ही उनकी दक्षता और मेहनत को खत्म कर दिया। आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए तीन खास क्षेत्रों पर असरदार तरीके से काम करने की जरूरत है। पहला, घरेलू मांग को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना। दूसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा उथल–पुथल को देखते हुए, जिसमें कई मुक्त व्यापार समझौते हो रहे हैं, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री को कस्टम ड्यूटी के ढांचे को सही बनाने और सुधारने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।तीसरा, कई प्रोत्साहनों के बावजूद, उद्योग और अर्थव्यवस्था के मूलभूत क्षेत्र (कोर सेक्टर) सुस्त साबित हो रहे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने के लिए भारत के उद्योग क्षेत्र को दो अंकों के विकास दर के करीब होना चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए इन पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। अब, महंगाई कोई सिरदर्द नहीं रही कृ महंगाई के मौजूदा रास्ते एक बहुत बड़ा मौका देते हैं। अक्टूबर 2024 में शीर्ष पर जाने के बाद से, महंगाई में गिरावट आई है। पिछले कुछ महीनों से, यह रिजर्व बैंक के सह्य सीमा 4प्रतिशत से कुछ नीचे है।महंगाई में गिरावट के इस माहौल में, वित्त मंत्री खर्च बढ़ा सकती हैं। वह मांग बढ़ाने के लिए कई बड़ी परियोजनाएं शुरू कर सकती हैं। वह ज्यादा निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कम ब्याज दर की उम्मीद कर सकती हैं। असल में, अपने कैबिनेट साथी, नितिन गडकरी के साथ मिलकर, वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण, ज्यादा बड़ी रोड बनाने का काम भी शुरू कर सकती हैं। रेलवे पहले से ही अपने हाई–स्पीड रेल नेटवर्क और रेल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में दूसरी चीजें जोड़ रहा है। ऐसी बड़ी परियोजनाएं और अवसंरचना बनाने से आज के मुख्य मैक्रो–इकानॉमिक मुद्दों में से एक का हल निकल सकता हैकृ जैसे कि घरेलू मांग को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था में ज्यादा निवेश स्तर बनाए रखना। नए आंकड़े और वैश्विक अर्थव्यवस्था बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए घरेलू मांग सबसे अच्छा तरीका है। अनिश्चित वैश्विक हालात को देखते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू बाजार पर भरोसा करना चाहिए और विकास को बढ़ाने वाले मुख्य इंजन के तौर पर घरेलू मांग को बढ़ाने की रणनीति एक सुरक्षित दांव है। कर्ज के लिए कम ब्याज दर और आसान उपभोक्ता ऋ ण, पूंजी लाभ पर कर पर फिर से विचार और जमीन–जायदाद बाजार के आसान नियम और अवसंरचनात्मक विकास घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए अहम हो सकते हैं। अगर घरेलू मांग अर्थव्यवस्था की रफ्घ्तार को काफी तेजी से बढ़ा रही है, तो वैश्विक माहौल उथल–पुथल वाला है। भारत को अपने बाहरी आर्थिक रिश्तों के लिए अपने पूरे फ्रेमवर्क को नये सिरे से बनाना होगा। मुक्त व्यापार समझौता अब तेजी से हो रहे हैं, जिनमें सबसे नया यूरोपियन यूनियन के साथ है। यह सबसे नया मुक्त व्यापार समझौता खास तौर पर मुश्किल है। यह कम से कम दो दशकों से बन रहा था। फिर भी, अचानक यह जादू की तरह

हो गया। सभी मुश्किल मुद्दे भुला दिए गए और समझौता हो गया। ऊपर से देखने पर, यह आर्थिक रणनीति के ठोस हिस्से के बजाय मुख्य रूप से एक राजनयिक उपकरण के तौर पर काम का लगता है। इसलिए, बजट में बाकी दुनिया के साथ भारत के रिश्तों को नये सिरे से बनाने में मदद के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। यह एक बहुत बड़ी कोशिश साबित हो सकती है। एक तो, उत्पाद और उत्पादन श्रृंखला में उनकी जगह के हिसाब से टैरिफ के पूरे सेट की फिर से जांच होनी चाहिए। उत्पादन–उपभोग के गणित में उनकी जगह के हिसाब से वस्तुओं पर टैरिफ के ढांचे का गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए। हमारे पास उल्टे टैरिफ के कई उदाहरण हैंकृ यानी, जिसमें अन्तिम उत्पादनों पर माध्यमिक उत्पादनों के मुकाबले कम टैरिफ लगते हैं। ये बाहर बने सामान के उपभोग को बढ़ावा देते हैं और देश में उसी के उत्पादन को हतोत्साहित करते हैं। इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए एक काम शुरू किया जाना चाहिए। बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी कमजोरियों और कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए। कई कोशिशों और प्रोत्साहनों के बावजूद, विनिर्माण उद्योग और मूलभूत क्षेत्रों के खिलाड़ी अभी भी पीछे हैं। औद्योगिक क्षेत्र ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर उस महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में जिसे हम पूरा कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में विकास अक्टूबर 2025 में 0.4 प्रतिशत तक कम हो गई।

बंदियों के फरार मामले में एक और डिप्टी जेलर व दो जेल वार्डर सस्पेंड अब तक 14 पर कार्रवाई

लखनऊ, (संवाददाता)। अयोध्या जेल से दो बंदियों के फरार होने के मामले में डीजी जेल ने एक

और डिप्टी जेलर को निलंबित किया है। साथ ही शनिवार को दो और जेल वार्डर सस्पेंड कर दिए गए हैं। उपमहानिरीक्षक कारागार, अयोध्या परिक्षेत्र की जांच आख्या के आधार पर राजू उर्फ राजदीप, उप कारापाल, हेड जेल वार्डर प्रभुनाथ कुमार व जेल वार्डर दीपक कुमार पांडेय को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। जिला जेल अयोध्या से 28 जनवरी की रात बैरक की दीवार में सेंध लगाकर दो बंदी फरार हो गए थे। इसमें अमेठी के मुसाफिरखाना का गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज और सुल्तानपुर का शेर अली शामिल था। दोनों पर हत्या, डकैती, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। प्रकरण में डीआईजी जेल अयोध्या रेंज शैलेंद्र कुमार मैत्रेय की रिपोर्ट पर जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा, जेलर जितेंद्र कुमार यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी, हेड जेल वार्डर हरिहर प्रसाद व त्रिपुरारी मिश्र और जेल वार्डर सुरेश कुमार दुबे, जयप्रकाश यादव, सुनील कुमार, रमेश सहानी, रवि यादव व मनोज को निलंबित कर दिया गया था। अब शुक्रवार को एक अन्य डिप्टी जेलर राजू उर्फ राजदीप को भी निलंबित कर दिया गया है। साथ ही हेड जेल वार्डर श्रप्रभुनाथ कुमार व जेल वार्डर दीपक कुमार पांडेय को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। डीआईजी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि रोजाना शाम को चेकिंग होने के बाद ही बंदियों को बैरकों के भीतर किया जाता है। जांच में सामने आया कि फरार हुए बंदी अपने साथ कोई उपकरण ले गए थे, जिसकी मदद से दीवार की ईटों को निकाला और वहां से भाग निकले। इससे स्पष्ट हुआ कि बैरक में भेजने से पहले इनकी चेकिंग नहीं की गई थी। चेकिंग की जिम्मेदारी डिप्टी जेलर राजू की थी। इस लापरवाही की वजह से उनको निलंबित किया गया है। डीजी जेल पीसी मीणा ने बताया कि प्रकरण में एक और डिप्टी जेलर की लापरवाही उजागर हुई है। इसलिए उसको निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। गहनता से मामले की जांच जारी है। जो भी दोषी होंगे उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी।

रेस्टोरेंट के सामने रिटायर्ड सैन्यकर्मी को युवक ने मारी गोली

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार की रात रिटायर सैन्यकर्मी को एक युवक ने गोली मार दी। इसके बाद फरार हो गया। सूचना पर डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल, एडीसीपी रल्लापल्ली वसंथ

कुमार, एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव व इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घायल को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित शॉपिंग स्क्वायर के बाहर की है। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल के मुताबिक, अवधेश पाठक (61) वायुसेना से रिटायर्ड हैं। वह असंल के सेक्टर–डी स्थित शॉपिंग स्क्वायर में रेस्टोरेंट चलाते हैं। शुक्रवार रात करीब 10रू30 बजे रेस्टोरेंट के बाहर कार में कुछ सामान रख रहे थे। इसी समय पीछे से आए युवक ने उन पर गोली चला दी।

संक्षिप्त खबरें

प्रो. आरपी और डॉ. अलका सिंह को मेंटल हेल्थ में नवाचार के लिए मिला पेटेंट

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के प्रो. आरपी. सिंह को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण नवाचार के लिए पेटेंट मिला है। उनका डिवाइस डिजाइन–सेल्फ रिफ्लेक्शन बेस्ड डायरी फॉर मेंटल वेलनेस ट्रैकिंग, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के आकलन और निगरानी में उपयोगी साबित होगा। इस शोध में डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की शिक्षिका डॉ. अलका सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके साथ अध्येता जॉय चौहान भी शोध टीम का हिस्सा रहे। यह नवाचार आज के तनावपूर्ण और तेज रफ्तार जीवन में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और देखभाल की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस मॉडल के जरिये व्यक्ति की दैनिक सोच, भावनाओं और व्यवहार का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया न केवल आत्मविश्लेषण को बढ़ावा देगी, बल्कि व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपयोगी और निदानात्मक साहित्य पढ़ने के लिए भी प्रेरित करेगी।

फुटबॉल की उभरती प्रतिभाओं की तलाश

लखनऊ, (संवाददाता)। शहर के ऐशबाग क्षेत्र में स्थित गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इंटर कॉलेज में शुक्रवार से फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन शिविर लगाया गया है। फीफा के तत्वावधान में ऑल इंडिया फुटबॉल की ओर से आयोजित इस शिविर में 12 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के 300 खिलाड़ी अब तक शामिल हो चुके हैं। इस टैलेंट सर्च प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य देश की भावी राष्ट्रीय टीम के लिए प्रतिभाओं को तराशना है। चयनित खिलाड़ियों को निशुल्क स्कॉलरशिप के साथ उच्च स्तरीय हॉस्टल सुविधा और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। शिविर का उद्घाटन कॉलेज के प्रधानाचार्य आलोक कुमार मिश्र ने किया।

समय पर जांच व एचपीवी वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव

लखनऊ, (संवाददाता)। महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से महाराजा बिजली पासी राजकीय पीजी कॉलेज, आशियाना में सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चिल्ड्रेन अनबाउंड फाउंडेशन ने स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से हुआ। एसजीपीजीआई की डॉ. इंदुलता ने बताया कि समय पर जांच और एचपीवी वैक्सीन से इस बीमारी से बचाव संभव है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जोनल हेड एपी सिंह ने बताया कि एचपीवी संक्रमण लड़कियों और लड़कों दोनों को प्रभावित करता है और यह सर्वाइकल सहित कई अन्य कैंसर से जुड़ा है। सीडीआरआई की डॉ. प्रियंका मौर्य व कॉलेज की प्राचार्य प्रो. सुमन गुप्ता ने भी बात रखी। कार्यक्रम में सर्वाइकल कैंसर सर्वाइवर सुषमा नौटियाल ने अपनी प्रेरणादायक कहानी साझा की। सेमिनार में पांच सौ से अधिक छात्राओं ने हिस्सा लिया।

भाषा विवि में रोबोटिक्स पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में शुक्रवार को रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईसीआरएएमई–2026 की शुरुआत हुई। इसमें देश–विदेश के शोधकर्ता, शिक्षक और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय तनेजा और एकेटीयू के कुलपति प्रो. जेपी. पांडेय ने दीप जलाकर किया। मुख्य अतिथि प्रो. पांडेय ने कहा कि रोबोटिक्स और ऑटोमेशन भविष्य की तकनीक हैं, जो काम को आसान बनाने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगी। कुलपति प्रो. तनेजा ने कहा कि यह सम्मेलन नई तकनीकों पर सीखने और विचार साझा करने का अच्छा मंच है। सम्मेलन में छह से अधिक देशों के 75 से ज्यादा शोध पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

161 भारतीय मजदूरों ने वीडियो जारी कर मांगी मदद भूखे-प्यासे तड़प रहे

लखनऊ, (संवाददाता)। सऊदी अरब के अबहा शहर में उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के 161 मजदूर गंभीर संकट में फंसे हुए हैं। इनमें अंबेडकरनगर जिले के भी नौ मजदूर शामिल हैं। पिछले तीन महीनों से इन मजदूरों को न तो वेतन दिया गया है और न ही पर्याप्त भोजन। दाने–दाने को तरस रहे इन मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। इन मजदूरों में बसखारी ब्लॉक के अमिया वामनपुर गांव के संतोष कुमार, ह्रदेश कुमार के अलावा फूलबदन निवासी नैपुरा आलापुर, अजय चौहान निवासी जैती जहांगीरगंज, वीरेंद्र कुमार निवासी औरंगाबाद इल्तिफातगंज, विजयपाल निवासी दुर्गापुर करमपुर, विजय बहादुर निवासी खुज्जीपुर जहांगीरगंज, सुरेश निवासी सहिजना हमजापुर आलापुर, सूरजभान निवासी बनगांव आंशिक अकबरपुर शामिल हैं। अमिया वामनपुर निवासी ह्रदेश के भतीजे सोनू राजभर ने बताया कि मजदूरों का वीजा छह माह पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन कंपनी उन्हें वापस नहीं भेज रही है। कंपनी उनसे जबरन पेंटिंग का काम ले रही है। स्थिति इतनी दयनीय है कि भारत में रह रहे गरीब परिजन खुद तंगी में होने के बावजूद वहां फंसे अपनों को खाने–पीने के लिए पैसे भेज रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कई समाजसेवी संगठनों ने विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास से संपर्क साधा है। अंबेडकरनगर के अलावा गोरखपुर, संतकबीरनगर, लखनऊ, लखीमपुर, आजमगढ़ और बस्ती के मजदूर भी इस समूह में शामिल हैं। परिजनों और मजदूरों ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर सभी

भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जाए। सऊदी अरब में आजीविका कमाने गए मजदूरों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहां फंसे मजदूर और यहां उनके परिजन, दोनों ही सुरक्षित घर वापसी के लिए सरकार की ओर ताक रहे हैं। जब तक उनकी वापसी सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक इन परिवारों के लिए चौन की रोटी नसीब होना मुश्किल लग रहा है। अकबरपुर जिला मुख्यालय से करीब 19 किलोमीटर दूर स्थित अमिया बामनपुर गांव के ह्रदेश कुमार वहां गंभीर संकट में हैं। उनके पिता राममिलन ने बताया कि ह्रदेश घर लौटना चाहते हैं, लेकिन कंपनी ने उनका पासपोर्ट अपने पास जमा कर रखा है। इसी गांव के संतोष की स्थिति भी चिंताजनक है। परिजनों के अनुसार, शुरुआत के एक–दो महीने तो सब ठीक रहा और उन्होंने पैसे भी भेजे, लेकिन धीरे–धीरे हालात बिगड़ते गए। आज स्थिति यह है कि मजदूरों के पास भोजन तक के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचे हैं। परिजनों की करुण पुकार है कि जब वहां कमाई ही नहीं हो रही, तो उन्हें हर हाल में वापस लाया जाए। ह्रदेश कुमार के घर में बुजुर्ग माता–पिता के अलावा पत्नी और दो छोटे बच्चे (12 और 8 वर्ष) उनकी राह देख रहे हैं। वहीं संतोष के परिवार में माता–पिता, पत्नी और तीन बच्चे हैं, जिनका भरण–पोषण संतोष के भरोसे ही था। सामाजिक कार्यकर्ता आबिद हुसैन (बजरंगी भाईजान) ने सऊदी अरब में फंसे मजदूरों से फोन पर सीधे बातचीत की। मजदूरों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए उनसे मदद की अपील की है। आबिद हुसैन ने बताया कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और जेद्दा (सऊदी अरब) स्थित भारतीय दूतावास को प्रेषित कर दी है।

संक्षिप्त खबरें

शकुंतला विवि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक व शोधार्थी हुए सम्मानित

लखनऊ, (संवाददाता)। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अकादमिक एक्सीलेंस अवॉर्ड्स2025 के तहत शुक्रवार को उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों, शोधार्थियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कुलपति आचार्य संजय सिंह ने चयनित प्रतिभागियों को सम्मान–पत्र देते हुए उनके शैक्षणिक, शोध, अकादमिक और गैर–शैक्षणिक योगदान की सराहना की। प्रवक्ता प्रो. यशवंत वीरोदय ने बताया कि विज्ञान, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी संकाय के प्रो. सीके. दीक्षित को उनके दीर्घकालीन शिक्षण और शोध योगदान के लिए सम्मान मिला। एसोसिएट प्रोफेसर श्रेणी में डॉ. कौशिकी सिंह और डॉ. विनोदिनी कटियार को सम्मानित किया गया। सहायक आचार्य वर्ग में डॉ. पुष्पेंद्र सिंह, डॉ. संजय कुमार, डॉ. महेश कुमार चौधरी और डॉ. श्याम सिंह को उनके उत्कृष्ट अकादमिक और शोध कार्यों के लिए सम्मान प्रदान किया गया। शोध श्रेणी में अर्चना कश्यप और रयान जे. लिवर्न को उनके शोध योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं गैर–शैक्षणिक संवर्ग में सब इंस्पेक्टर दयाशंकर, वैयक्तिक सहायक सुशील कुमार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सूरज पाल को सम्मान मिला।

38 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को मिली नौकरी

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर स्थित लखनऊ राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर में शुक्रवार को कैंपस ड्राइव का आयोजन हुआ। नोएडा की महालय कंपनी की ओर से अप्रेंटिसशिप और जूनियर इंजीनियर के पद पर हुए साक्षात्कार में 38 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को 17 हजार रुपये महीने के मानदेय पर चयनित किया गया। कंपनी की ओर से रहने और खाने की सुविधाएं भी दी जाएंगी। साथ ही मशीन ऑपरेटर का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पॉलीटेक्निक के प्लेसमेंट अधिकारी डॉ. सत्य प्रकाश सोनी ने बताया कि संस्थान से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बड़ा अवसर मिला है। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें देश की प्रसिद्ध कंपनी में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिला। कंपनी की ओर से करीब 60 पदों के लिए साक्षात्कार लिए गए थे इनमें 50 करीब विद्यार्थी शामिल हुए।

'स्क्रीन से पन्नों की ओर उत्सव–2026' के जरिए किताबों से जोड़ेगा माध्यमिक शिक्षा विभाग

लखनऊ, (संवाददाता)। माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश विद्यार्थियों में पठन–पाठन की रुचि को सुदृढ़ करने और 'पठन अभियान' को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 03 फरवरी 2026 को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, लखनऊ में "स्क्रीन से पन्नों की ओर उत्सव–2026" का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन विद्यार्थियों को डिजिटल स्क्रीन की दुनिया से बाहर निकालकर पुस्तकों और साहित्य की ओर आकर्षित करने की अभिनव पहल के रूप में देखा जा रहा है।कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से एक भव्य पुस्तक प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें राजकमल, वाणी, नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रभात सहित देश के प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा पुस्तक स्टॉल लगाए जाएंगे। इस प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों को साहित्य, ज्ञान–विज्ञान, सामान्य अध्ययन और रचनात्मक लेखन जैसी विविध विधाओं की पुस्तकों से परिचित है।

बच्चों को किताब व अखबार से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे विशेषज्ञ

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी सहित प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पहली बार राज्य स्तरीय पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्क्रीन से दूर रखकर पठन संस्कृति को बढ़ावा देना और किताबों के साथ–साथ अखबार पढ़ने की आदत विकसित करना है। मेले में विद्यार्थियों को उनकी जरूरत की किताबें 15 से 20 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि सिटी स्टेशन मार्ग स्थित राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज परिसर में तीन फरवरी को माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से मेगा पुस्तक मेले का आयोजन होगा। मेले में विभिन्न विशेषज्ञ बच्चों को किताबों और अखबार पढ़ने के महत्व के प्रति जागरूक करेंगे। राज्य पुस्तकालय की विशेष कार्याधिकारी सांत्वना तिवारी ने बताया कि पुस्तक मेले में 15 से 20 प्रकाशक भाग लेंगे। प्रत्येक स्टॉल पर 1200 से 1500 पुस्तकें उपलब्ध होंगी, जो किफायती दामों पर दी जाएंगी। मेले में कहानी, लोककथाएं, लोक कलाएं और स्वावलंबन से जुड़ी पुस्तकें प्रमुख रूप से शामिल रहेंगी। मेले की थीम 'स्क्रीन से पठन की ओर, संस्कृति अध्ययन की पहल' रखी गई है। सांत्वना तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव के अलावा स्टोरी टेलर, वरिष्ठ साहित्यकार, पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। वे विद्यार्थियों को संघर्ष से सफलता तक की प्रेरक कहानियां सुनाने के साथ–साथ तनावमुक्त बोर्ड परीक्षा की तैयारी के टिप्स देंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार, पुस्तक मेले में शैक्षणिक पुस्तकों के साथ–साथ पेंटिंग और रेखाचित्रों से जुड़ी किताबें भी उपलब्ध होंगी। यहां साहित्य, फिक्शन, नॉन–फिक्शन, नए व प्रसिद्ध लेखकों की साइन की गई प्रतियां, रहस्य, रोमांस, ऐतिहासिक उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, विज्ञान, इतिहास, आत्मनिर्भरता और यात्रा वृत्तांत पर आधारित पुस्तकें मिलेंगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की गाइड, भाषा सीखने की किताबें तथा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों की रुचि के अनुसार कहानियां, नाटक, उपन्यास और कविताएं भी उपलब्ध रहेंगी।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण को और प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान मॉडल का अध्ययन

लखनऊ, (संवाददाता)। योगी सरकार दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर ठोस व संवेदनशील प्रयास कर रही है। प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़, आधुनिक एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की सफल और नवाचारपूर्ण योजनाओं का अध्ययन कर उन्हें उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों के अनुरूप लागू किया जा रहा है।इसी क्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने 28 से 30 जनवरी 2026 तक राजस्थान का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के क्षेत्र में संचालित योजनाओं, संस्थागत व्यवस्थाओं और नवाचारों की गहन समीक्षा की। जयपुर स्थित सर्किट हाउस में प्रमुख सचिव एवं निदेशक स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की कार्यप्रणाली, लाभार्थी चयन, तकनीकी सहायता, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तथा पुनर्वास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश में संचालित योजनाओं के साथ तुलनात्मक विमर्श किया गया, जिससे प्रदेश में योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।जयपुर प्रवास के दौरान मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विधानसभा की कार्यप्रणाली, संसदीय परंपराओं, जनहित से जुड़े विषयों और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर सार्थक चर्चा हुई। मंत्री कश्यप ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का मार्गदर्शन सदैव प्रेरणादायी होता है और जनसेवा व लोकतंत्र के प्रति उनका समर्पण सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है।भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्री कश्यप ने जयपुर स्थित भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने संस्थान द्वारा दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता के कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। मंत्री कश्यप ने कहा कि यह संस्था सेवा, संवेदना और समर्पण की जीवंत मिसाल है।

मधुबन में पहली बार आयोजित हुआ रोजगार मेला, युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ जनपद के मधुबन स्थित गांधी मैदान में आयोजित रोजगार मेला में प्रतिभाग कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मधुबन के इतिहास में यह पहला अवसर है जब रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जो क्षेत्र के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।उन्होंने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को रोटी–रोजगार से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को उनके ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। इसी क्रम में परदहा की बंद पड़ी मिल को औद्योगिक संकुल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के माध्यम से लोग स्वयं का रोजगार स्थापित कर आजीविका चला सकते हैं। केवल मधुबन क्षेत्र में ही लगभग 700 लोगों को पौने दो करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें।उन्होंने कहा कि पहले वैश्विक स्तर की बड़ी कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित नहीं करती थीं, लेकिन वर्तमान नेतृत्व के कारण आज देश में, विशेषकर बेंगलुरु जैसे शहरों में, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित हो रही हैं। इससे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। मंत्री ने चयनित सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संबंध में उन्होंने बताया कि मधुबन क्षेत्र में लगभग 700 आवास आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 80 से अधिक लाभार्थियों के खातों में धनराशि पहुंच चुकी है, जबकि शेष लाभार्थियों के खातों में भी शीघ्र ही राशि भेजी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किसी भी स्तर पर कोई धनराशि नहीं देनी होती है और जिन पात्र लोगों के पास आवास नहीं है, उन्हें निश्चित रूप से योजना का लाभ मिलेगा।विद्युत व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि मधुबन क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नए विद्युत स्टेशन बनाए गए हैं तथा कई सब–स्टेशनों की क्षमता का विस्तार किया गया है। विद्युत बिल राहत योजना के अंतर्गत मधुबन में 918 कैंप लगाए गए, जिनमें 14,644 लोगों को लाभ मिला और लगभग 25 करोड़ रुपये की बचत हुई। वहीं पूरे मऊ जनपद में अब तक 3,500 कैंप आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से हजारों उपभोक्ताओं को लगभग 75 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई है।रोजगार मेला के दौरान चयनित अभ्यर्थियों प्रीति कुमारी, अंशु कुमार, अशोक कुमार, सुनील कुमार यादव, अनिल कुमार, रोशन कुमार, अर्जुन सोनकर एवं सुनील सोनकर को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गिरिजा देवी, तेतरी, वेद प्रकाश साहनी, माधुरी ममता, तारा देवी, सीमा मौर्य, महिमा भारती सहित अन्य लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

उड़ीसा में यूपी आलू के विपणन को नई गति

लखनऊ, (संवाददाता)। उड़ीसा राज्य में उत्तर प्रदेश के आलू के संगठित और व्यापक विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) के संयुक्त तत्वावधान में भुवनेश्वर स्थित होटल द प्रेसीडेंसी में एकदिवसीय आलू प्रदर्शनी एवं बायर–सेलर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह तथा उड़ीसा सरकार के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव मुख्य रूप से उपस्थित रहे।इस अवसर पर उड़ीसा राज्य से कलुंगे गोरख वामन, धारित्री मिश्रा (एसएजी), जनरल मैनेजर (ओएसएएम बोर्ड) तथा उत्तर प्रदेश से हाफेड के प्रबंध निदेशक डॉ. सर्वेश कुमार, संयुक्त निदेशक शाकभाजी डॉ. राजीव कुमार वर्मा, नोडल अधिकारी हाफेड एस.के. सुमन सहित दोनों राज्यों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 11 आलू उत्पादक किसानों तथा उड़ीसा राज्य के 47 आलू व्यापारियों, निर्यातकों और प्रसंस्करण इकाइयों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है, जहां देश के कुल आलू उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा उत्पादित होता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025–26 में प्रदेश में लगभग 6.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 245.94 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन संभावित है। प्रदेश का लगभग 60 प्रतिशत आलू आगरा, अलीगढ़, मेरठ और कानपुर मंडल के 10 जनपदों में उत्पादित होता है। उन्होंने कहा कि कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, कुफरी सिन्दूरी, कुफरी पुखराज, कुफरी चिप्सोना और फ्राईसोना जैसी उन्नत प्रजातियां दूरस्थ विपणन है।

मैत्री क्रिकेट मैच में जर्नलिस्ट टीम का दबदबा, जलालपुर पुलिस 62 रन से पराजित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। खेल के मैदान पर सौहार्द, भाईचारे और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की मिसाल उस समय देखने को मिली, जब पराऊगंज स्थित एक स्कूल के मैदान पर जर्नलिस्ट क्रिकेट टीम और जलालपुर पुलिस टीम के बीच मैत्री क्रिकेट मुकाबला खेला गया। रोमांचक मुकाबले में जर्नलिस्ट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जलालपुर पुलिस को 62 रनों से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जर्नलिस्ट टीम के कप्तान राजन मिश्रा ने लिया, जो पूरी तरह सही साबित हुआ। 12 ओवर के इस मुकाबले में पत्रकारों की टीम ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए मात्र दो विकेट के नुकसान पर 240 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ओपनिंग बल्लेबाज शिवम उपाध्याय हरिया और सरस सिंह ने पुलिस के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार

किया। शिवम उपाध्याय हरिया ने शानदार शतक जड़ते हुए 105 रन बनाए, जबकि सरस सिंह ने भी विस्फोटक अंदाज में 100 रनों की पारी खेली। आलोक सिंह ने नाबाद 32 रनों का योगदान दिया। टीम को 3 रन अतिरिक्त के रूप में प्राप्त हुए। 240 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी महेंद्र यादव की कप्तानी वाली जलालपुर पुलिस टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी। संजय प्रजापति ने एक छोर से संघर्ष करते हुए 90 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सके। निर्धारित 12 ओवर में पुलिस टीम 8 विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना सकी। गेंदबाजी में जर्नलिस्ट टीम की ओर से आलोक सिंह ने 3 विकेट झटके। शिवम उपाध्याय हरिया और इमरान अब्बास को 2–2 विकेट मिले, जबकि सुशील तिवारी ने 1 विकेट हासिल किया। शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए शिवम उपाध्याय हरिया को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच के दौरान अंकित जायसवाल की रोचक और जीवंत कमेंट्री ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। मुकाबले के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में कोच मोहम्मद अब्बास, संरक्षक पंकज भूषण मिश्रा तथा प्रभारी निरीक्षक जलालपुर गजानंद चौबे ने दोनों टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जर्नलिस्ट क्रिकेट टीम में अजीत सिंह, देवेंद्र खरे, सुशील तिवारी, राजन मिश्रा, आलोक सिंह, मसूद अहमद, इमरान अब्बास, शिवम उपाध्याय हरिया, शिवेंद्र प्रताप सिंह 'काजू', सरस सिंह, विवेक सिंह और अरशद अब्बास शामिल रहे। वहीं जलालपुर पुलिस टीम की ओर से महेंद्र यादव, संतोष मिश्रा, अरविंद कुमार, रजत पांडेय, अमन कुमार, अजीत कुमार, धीरेन्द्र निषाद, अभिषेक शर्मा, सुरेश सिंह, संजय प्रजापति और सरफराज कर्णधीर पाल ने सहभागिता निभाई। मैच के दौरान पत्रकार संतोष राय और प्रदीप सिंह की मौजूदगी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। यह मैत्री मुकाबला खेल के माध्यम से आपसी सहयोग, सौहार्द और सकारात्मक संबंधों का प्रतीक बनकर सामने आया।

जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम एवं कृषि विभाग को सभी किसानों की आईडी बनवाने के दिए निर्देश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की अगली किश्त पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना की अगली किश्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराया होगा। किसानों को जागरूक करने के लिए कैंप लगेंगेरू उन्होंने जिलाधिकारियों से व्यक्तिगत रुचि लेकर इस कार्य में तेजी लाने को कहा मुख्य सचिव ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण को त्वरित गति से पूरा किया जाए। किसानों को जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएं और रजिस्ट्री टीमों को सक्रिय रखा जाए। पूर्ण पारदर्शिता और सतर्कता बरतते हुए सुनिश्चित किया जाए कि कोई पात्र किसान रजिस्ट्री के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहे। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगीरू बैठक में बताया गया कि जनपद में पीएम किसान के कुल 879354 लाभार्थियों में से अब तक 537530 (61.13:) किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री कराई है शेष किसानों की फार्मर रजिस्ट्री 31 मार्च 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिया गया है। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं उप कृषि निदेशक को पत्र लिखकर प्रति तहसील प्रतिदिन सर्वोच्च प्राथमिकता के दृटिगत 1500 फार्मर रजिस्ट्री बनवाने का निर्देश दीए है ताकि कोई भी पात्र कृषक योजना से वंचित न हो सकें।

संक्षिप्त खबरें

कोडीन कफ सिरप आरोपियों की एसआईटी जब्त करेगी संपत्ति, जांच में नहीं किया सहयोग : गोल्डी गुप्ता एसआईटी प्रमुख

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शिकंजा कसा है। इस मामले में शनिवार को 22 आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। अब जल्द ही उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल और उनके पिता भोला जायसवाल ने रांची स्थित शैली ट्रेडर्स से जौनपुर समेत अन्य जिलों में भारी मात्रा में कोडीनयुक्त कफ सीरप की आपूर्ति की थी। पिता–पुत्र के खिलाफ कोतवाली में भी मुकदमा दर्ज है। भोला जायसवाल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में सहारनपुर के अशोक विहार कॉलोनी निवासी विशाल उपाध्याय, ने कोतवाली के चितरसारी शकरमंडी निवासी आकाश मौर्या व अरुण सोनकर, जमालपुर निवासी शिवम मौर्या, डालगर टोला निवासी अंकित कुमार श्रीवास्तव, संजीव कुमार चौरसिया, सुजानगंज के बलवरगंज निवासी सौरभ गुप्ता, अरुण प्रकाश मौर्या, बलुआघाट निवासी ओमप्रकाश मौर्या और सरायख्वाजा के सर्फराजपुर निवासी अनुप्रिया सिंह सहित अन्य के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही सभी आरोपित फरार हैं। नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई भी आरोपित जांच में सहयोग करने या हाजिर होने के लिए नहीं आया। इस मामले में रविवार को जानकारी लेने पर एसआईटी प्रमुख सहायक पुलिस अधीक्षक गोल्डी गुप्ता ने बताया कि कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी के मामले में जिले के 22 आरोपितों के विरुद्ध शनिवार को गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। उन्होंने पुष्टि किया कि आरोपितों द्वारा समय दिए जाने के बाद भी जांच में सहयोग न करने या हाजिर न होने के कारण अब उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जल्द ही की जाएगी।

18 लाख के 111 गुमशुदा मोबाइल फोन पुलिस ने जनपद और आसपास के जिलों से किया बरामद उनके स्वामियों को सौंपा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम ने सीईआईआर (ब्म्प्ट) पोर्टल के माध्यम से 111 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों का कुल बाजार मूल्य लगभग 18 लाख रुपये आंका गया है। बरामद किए गए मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए गए हैं। मामले का सोमवार को खुलासा करते हुए एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि गुमशुदा मोबाइलों के प्रार्थना पत्रों और सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर, साइबर क्राइम थाना जौनपुर की पुलिस टीम ने इन फोनों का पता लगाया। बरामद किए गए 111 मोबाइल जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मिले हैं, जिनमें शाहगंज (19), खुटहन (04), कोतवाली (03), लाइनबाजार (03), सरायख्वाजा (03), तेजीबाजार (02), सरपतहाँ (03), सुजानगंज (03), मडियाहू (03), मुगराबादशाहपुर (02) और नेवडिया (01) शामिल हैं।इन मोबाइलों की बरामदगी केवल जौनपुर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों जैसे आजमगढ़, प्रयागराज, बहराईच, लखनऊ, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़ और भदोही से भी फोन बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त, कुछ मोबाइल फोन दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों से भी खोजे गए।बरामद किए गए मोबाइलों में मुख्यतः वन प्लस, वीवो, रेडमी, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, पोको, नोकिया और सैमसंग जैसी विभिन्न कंपनियों के फोन शामिल हैं। इन सभी मोबाइलों का कुल बाजार मूल्य लगभग 18 लाख रुपये है।बरामद किए गए मोबाइल फोन अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी सदर साइबर क्राइम देवेश सिंह द्वारा उनके स्वामियों को वितरित किए गए। अपने खोए हुए मोबाइल फोन वापस पाकर सभी धारक काफी संतुष्ट और प्रसन्न दिखे।इस अवसर पर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने जनता को सलाह दी कि मोबाइल फोन गायब होने की स्थिति में सबसे पहले थाने में गुमशुदगी दर्ज कराएं और उसके बाद सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। उन्होंने साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता को बचाव का सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया।उन्होंने यह भी बताया कि साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें इसके अलावा, नागरिक अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्पडेस्क पर पहुंचकर लिखित शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

जश्न रियल्टी ने लखनऊ में 3,200 करोड़ के निवेश की घोषणा की, तेज डिलीवरी सर्वोच्च प्राथमिकता

लखनऊ। जश्न रियल्टी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कंपनी के नेतृत्व ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजना साझा की। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री राहुल अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, जश्न रियल्टी, ने बताया कि कंपनी आगामी तीन वर्षों में रियल एस्टेट विकास क्षेत्र में लगभग 3,200 करोड़ का निवेश करने जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान श्री अग्रवाल ने कहा कि जशन रियल्टी की विस्तार रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय और मिक्स्ड–यूज प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित होगी, जो लखनऊ जैसे टियर–प्प् शहरों में बढ़ती मांग के अनुरूप हैं। उन्होंने शहर के तेजी से विकसित होते इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और बढ़ते निवेशकों के विश्वास को इस बड़े निवेश निर्णय के प्रमुख कारण बताया। श्री राहुल अग्रवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजनाओं की तेज और समयबद्ध डिलीवरी कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, "समय से पहले और तेज डिलीवरी अब केवल एक अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है। जशन रियल्टी में हम अपनी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं, निष्पादन टीमों को मजबूत बना रहे हैं और उन्नत निर्माण योजना को अपनाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स तय समय से पहले ग्राहकों तक पहुँचें।" कंपनी ने यह भी बताया कि आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स में ग्राहक–केंद्रित डिजाइन, नियामकीय अनुपालन और पारदर्शी निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जशन रियल्टी का लक्ष्य निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा और सतत विकास मानकों से समझौता किए बिना डिलीवरी टाइमलाइन में नए मानक स्थापित करना है। इस घोषणा को स्थानीय रियल एस्टेट जगत और मीडिया से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिससे जशन रियल्टी को लखनऊ के तेजी से विकसित हो रहे रियल एस्टेट परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक निवेशक के रूप में देखा जा रहा है।

बच्चों का भविष्य ही देश का भविष्य है- डॉ. अब्दुल कादिर खान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर–डालिम्स सनबीम स्कूल, जौनपुर के विद्यालय परिसर में गत रात्रि वार्षिक मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन अत्यंत उत्साह और रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं अतिथियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जिससे पूरा परिसर उत्सवमय वातावरण से सराबोर हो गया। यह आयोजन विद्यालय परिवार के लिए एक यादगार अवसर बन गया। कार्यक्रम की शोभा मुख्य अतिथि डॉ अब्दुल कादिर खान (अध्यक्ष, मोहम्मद हसन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप), विशिष्ट अतिथि जेएमएस ग्रुप के चेयरमैन जितेंद्र यादव तथा विशेष अतिथिगण डॉ. कमर अब्बास, डॉ. हैदर अब्बास, आर.पी. सिंह, हसनैन कमर दीपु एवं अहमद अब्बास खान की गरिमामयी उपस्थिति से और बढ़ी। अतिथियों की मौजूदगी ने विद्यार्थियों का उत्साह दोगुना कर दिया। विद्यार्थियों ने नृत्य, समूहगान, नाट्य मंचन एवं विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी प्रस्तुतियों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और मंच कौशल स्पष्ट रूप से झलक रहा था। सुसज्जित परिसर, आकर्षक खेल स्टॉल और मेले का उल्लासपूर्ण माहौल संध्या को और भी यादगार बना गया। मुख्य अतिथि डॉ अब्दुल कादिर खान ने अपने संबोधन में विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा समग्र शिक्षा के प्रति विद्यालय की प्रतिबद्धता को प्रेरणादायी बताया। विशिष्ट अतिथि जितेंद्र यादव ने भी विद्यार्थियों को अनुशासन, संस्कार और उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यालय द्वारा प्रदान किए जा रहे सकारात्मक एवं पोषणकारी शैक्षिक वातावरण की सराहना की। कार्यक्रम में विद्यालय के सम्मानित स्टाफ सदस्य नवाल अहमद, फातेमातुज्जेहरा, नेदा एवं सबा वाजिया सहित अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समारोह के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ अलका गुप्ता ने ध न्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अभिभावकों के विश्वास, विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी, अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति तथा शिक्षण एवं गैर–शिक्षण कर्मचारियों के अथक सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

संक्षिप्त खबरें

बाइक एजेंसी और कंप्यूटर सेंटर में चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

भदोही, (संवाददाता)। कोइरौना पुलिस ने टीवीएस बाइक की एजेंसी और कंप्यूटर सेंटर में हुई चोरी की घटना में शामिल नारेपार पैगहा निवासी सूरज तिवारी उर्फ बाबा व आनंद सिंह उर्फ अनुज को सीतामढ़ी से बृहस्पतिवार की रात में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बैटरी, सीलिंग फैन, इनवर्टर, हेलमेट, सीएफएल बल्ब, सोलर पैनल व चोरी में शामिल बाइक बरामद की है। महुआरी जंगीगंज निवासी विनय कुमार मिश्र ने बताया कि पैगहा नारेपार में उसकी टीवीएस बाइक की एजेंसी है। 22 और 23 सितंबर 2025 की रात में एजेंसी से बैटरी, इनवर्टर, हेलमेट, डिनर सेट, प्रेस, अपाचे बेलकम, राइडर वेलकम, एसोसीरिज स्मार्ट वाच, इयर बर्ड, नेक बैंड, पावर बैंक चोर उठा ले गए। वहीं हंडिया थाना के भेलसी निवासी अतुल कुमार कोईरौना थाने में तहरीर दी कि नारेपार पैगहा (सीतामढ़ी) धनतुलसी जंगीगंज मार्ग पर कंप्यूटर सेंटर चलाता है। 23 दिसंबर 2025 की रात चोरों ने ताला तोड़कर सेंटर में रखे दो बैटरी, दो इनवर्टर, कैमरा डीवीआर, दो सोलर पैनल, चार लैपटाप उठा ले गए। एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि दोनों को जेल भेजा दिया गया है। संवाद पुलिस ने गांवों से बकरी चुराने वाले तीन चोरों को शुक्रवार को पचपटिया गांव के पास से गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो बकरी, बाइक और छह हजार नकद बरामद किया। ममहर गांव निवासी जगराम गौतम ने 15 जनवरी 2026, चौरी खास के मिंटू सोनकर और मानिकपुर की मीरा देवी ने दो जनवरी को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि घर के बाहर टीनशेड में बांधी गई 12 बकरियां चोरी हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी गुड्डू गौतम और विक्रम गौतम निवासी नहवानीपुर जगदीशपुर कपसेठी वाराणसी और मुकेश नट लखनसेनपुर (शिवदासपुर) कपसेठी वाराणसी बाइक से बकरी चोरी किए थे।

शशांक इलेवन की टीम को हराकर सेवाश्रम कॉलेज फाइनल में पहुंचा

भदोही, (संवाददाता)। महर्षि आजाद स्टेडियम मेढ़ी में राज्यस्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट धीरे–धीरे समापन की ओर बढ़ गया है। शुक्रवार को टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला गया। इसमें शशांक इलेवन को हराकर सेवाश्रम इंटर कॉलेज मोढ़ ने फाइनल में जगह बना लिया। दूसरा सेमीफाइनल बांदा और रायबरेली के बीच शनिवार को खेला जाएगा। सेवाश्रम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए शशांक इलेवन की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाई। इसमें लक्ष्य यादव ने 56 गेंदों में 79 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जबकि मयंक दुबे ने 29 गेंदों पर 46 रन बनाकर अहम योगदान दिया। सेवाश्रम इंटर कॉलेज की ओर से संदीप गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीं, दीपक पटेल और सनी पांडेय ने 2–2 विकेट लेकर शशांक इलेवन की रन गति पर लगाम लगाई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेवाश्रम इंटर कॉलेज की टीम ने संयमित बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। टीम की ओर से अनुराग रघुवंशी ने 38 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेली। अंत में दुर्गा चरण ने 14 गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाकर टीम को 18.1 ओवर में 151ध्5 के स्कोर तक पहुंचाया और जीत दिलाई।

धर्मांतरण मामले में चार लोग गिरफ्तार पुलिस पूछताछ करने में जुटी होगी कड़ी कार्यवाही : आयुष श्रीवास्तव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर स्थित केराकत कोतवाली क्षेत्र के तरियारी गांव में रविवार को कथित मतांतरण की सूचना पर पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। पूछताछ के बाद महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया, जबकि सात पुरुषों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। नरहन गांव निवासी बाबा रामजनम नागर ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि तरियारी गांव में लंबे समय से मतांतरण से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस टीम ने गांव निवासी पुष्पा देवी के आवास पर दबिश दी। पुलिस के अनुसार मौके पर प्रार्थना सभा चल रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से कुछ धार्मिक पुस्तकें और फोटो सामग्री बरामद की है। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को दो पिकअप वाहनों से थाने लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। इस मामले में बाबा रामजनम नागर ने चार लोगों के खिलाफ मतांतरण कराने का आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर दी है। देर रात पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया, जबकि सात पुरुष अभी भी हिरासत में हैं। इससे पहले भी इस क्षेत्र में ध र्मांतरणत्र को लेकर काफी बवाल हुआ है पुलिस द्वारा कार्यवाही भी किया जाता है बावजूद इसके इलाके में इस तरह की गतिविधियों के संचालित होने से लोगों में रोष बना हुआ है। विदित हो कि इससे पहले भी जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में धर्मांतरणत्र के मामले सामने आते रहे है हाल के दिनों में बदलापुर कोतवाली थाना अंतर्गत और सिंगरामऊ कोतवाली अंतर्गत भी ध र्मांतरण के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था जिसको लेकर बजरंग दल के लोगो ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया था।इसी तरह लाइन बाजार थाना अंतर्गत रामदयाल गंज में पनिहवा बाबा के नाम से चल रहे ईसाई मिशनीरी से जुड़े और धर्मांतरणत्र करवा रहे चार पुरुषों और एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ध र्मांतरण के मामले में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि कल केराकत कोतवाली पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी तरियारी गांव में अजय कुमार गौतम द्वारा वहां के स्थानीय लोगों को बुलाया जा रहा है और प्रलोभन देकर धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही है तत्काल पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और एक पुलिस टीम तरियारी गांव पहुंची वहां पहुंचने पर देखा गया कि अजय कुमार गौतम के घर के पास ही स्थानीय लोग एकत्रित थे जो लगभग 25 से 30 की संख्या में थे उनके पास से बाइबल बैनर मिला है और उनको प्रलोभन भी दिया जा रहा था इसमें ईसाई धर्म अपनाने से क्या फायदा होगा इसके बारे में बताया जा रहा था अजय कुमार गौतम और इसके साथ तीन अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है आगे की कार्रवाई की जा रही है इस मामले में पुलिस बैक ट्रेकिंग करते हुए कि इस मामले में और किसी का इन्विलमेन्ट नहीं है इसकी भी जांच पड़ताल कर रही है। और इसमें उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

यह बजट देश की गति को तीव्रता से आगे बढ़ाएगा और आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा :गरीशचंद्र यादव राज्य मंत्री

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में केंद्रीय बजट पेश होने के बाद सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खेल कूद युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीशचंद्र यादव ने आज पेश हुए केंद्रीय बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट पिछले बजट की तुलना में लगभग 8ध अधिक है। यादव ने दावा किया कि यह बजट देश की गति को तीव्रता से आगे बढ़ाएगा और आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने बताया कि बजट सभी सेक्टरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मंत्री के अनुसार, यह बजट गांव के गरीब, नौजवान, किसान और महिलाओं के उत्थान पर केंद्रित है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने वाला बताया। विपक्ष द्वारा बजट को श्पूंजीपतियों का बजटश बताए जाने पर मंत्री गिरीशचंद्र यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वे मुद्दाविहीन लोग हैं। यादव ने आरोप लगाया कि देश की जनता द्वारा नकारे जाने के बाद से विपक्ष सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप–प्रत्यारोप कर रहा है। उन्होंने विपक्ष को हमेशा नकारात्मक टिप्पणी करने वाला बताया, जिनका देश के विकास से कोई सरोकार नहीं है। बजट अपनी प्रक्रिया देते हुए नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राधे रमण जायसवाल ने कहा कि बजट पूरी तरह से सभी को समावेशित करते हुए प्रस्तुत किया गया है व्यापारी ही तो प्रबुद्ध नागरिकों छात्रों महिलाओं और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है इस बजट से देश का चौहमुखी विकास दिखाई दे रहा है श्री जायसवाल ने कहा कि यह बजट समावेशी है व्यापारी वर्ग लिए यह बजट पूरी तरह से खरा नहीं उतर पा रहा है। फिर भी मुझे जैसी जानकारी मिली है कि इसमें रोजगार परक बजट में चर्चा किया गया है वित्त मंत्री द्वारा रोजगार सृजन के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है व्यापारियों की जो तमाम मांगी थी इनकम और आई को लेकर जो व्यापारी पर बात करता था उसे विषय को लेकर कहीं ना कहीं वह इस बजट में छूट गया है बी मंत्री जी को इस मामले में आगे जो भी संशोधन करना हो वह कृपया इस पर ध्यान रखेंगे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।